(ग) क्या यह भी सच है कि देश के अन्य शहरी क्षेत्रों की तुलना में व्यय में यह तेजी सबसे अधिक दिल्ली राज्य में हुई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी बढ़ोतरी का आकलन क्या है तथा उन क्षेत्रों के नाम क्या-क्या हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर औसतन दर से ऊपर आंके गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारियों (श०गै०श्र०क०) हेतु सांख्यिकी विभाग द्वारा संकलित 1984-85=100 पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों (उ०मू०सू०) ने जुलाई, 1998 में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी अखिल भारतीय स्तर पर दर्शाई है।

(ग) 59 शहरी केन्द्रों में जिनके लिए उ०मू०सू० (श०गै०श्र०क०) संकलित किया जाता है, चण्डीगढ़ केन्द्र ने सूचकांक में जुलाई, 1997 की तुलना में जुलाई, 1998 में 24.4 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्ज की है, इसके बाद दिल्ली केन्द्र ने सूचकांक में 20.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई है।

(घ) शहरी केन्द्रों का विस्तृत ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण, जिसमें उ०मू०सू० (श०गै०श्र०क०) जुलाई, 1997 की तुलना में अखिल भारतीय औसत की अपेक्षा जुलाई, 1998 में उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई है, नीचे दिया गया है।

विवरण

शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारियों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

क्र० सं०	केन्द्र के लिए सूचकांक		प्रतिशत वृद्धि
	जुलाई 1997	जुलाई 1998	
1. चण्डीगढ़	316	393	24.4
2. दिल्ली	281	339	20.6
3. गंगटोक	297	352	18.5
4. मेरठ	262	308	17.6
5. जबलपुर	276	323	17.0
6. शोलापुर	285	333	16.8
7. कुर्नूल	305	355	16.4
8. भोपाल	293	341	16.4
9. मुजफ्फरपुर	277	322	16.2
10. श्रीनगर	284	330	16.2
11. पूणे	287	331	15.3
12. जम्मू	292	336	15.1
13. ग्वालियर	304	350	15.1
14. खड़गपुर	275	316	14.9
15. पटना	283	325	14.8
16. भावनगर	303	346	14.2
17. आगरा	285	325	14.0
18. विशाखापतनम	302	343	13.6
19. अहमदाबाद	259	294	13.5
20. लखनऊ	288	326	13.2
समस्त भारत	**297**	**336**	**13.1**

Social security and medical facilities to elderly persons

1363. DR. ALLADI P. RAJKUMAR:
SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of adolesconts and elderly persons in the country as per recent report of the United Nations Population Fund;

(b) the steps proposed to create more jobs needed to accommodate young workers to reduce unemployment; and

(c) the measures proposed to provide social sescurity and adequate medical and financial facilities to elderly people?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) United Nations Population Fund publication "The State of World Population—The New Generations" 1998 does not indicate the number of adolescents and elderly persons in India. However, in the Report of the Technical Group on Population Projections published by the Registrar General of India in 1996 the number of adolescents

(10—19 years) and elderly population (65 years and above) as on 1st March, 1998 have been estimated to be 213.8 million and 42.2 million respesctively.

(b) One of the primary objectives of the Ninth Plan is to generate greater productive employment in the growth process itself by concentrating on sectors, sub-sectors and technologies which are more labour itensive in regions characterised by higher rates of unemployment and under employment.

(c) The schemes currently providing social and financial security to elderly people include old age pension provided by State Governments and under National Social Assistance Programme (NSAP), contributory and non-contributory provident funds. Health care to the elderly is provided through existing network of primary, secondary and tertiary health care institutions. During Ninth Five-Year Plan the coverage under all these will be further improved.

उत्तर प्रदेश में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम॰पी॰एल॰ए॰डी॰एस॰) के लिए स्वीकृत धनराशि

1364. **श्री मुनव्वर हसन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सांसद को "संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना" के अन्तर्गत कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) 31 मार्च, 1998 तक इनमें से प्रत्येक संसद-सदस्य द्वारा कितनी राशि खर्च की गई और कितनी राशि शेष है;

(ग) लोक सभा चुनाव हार चुके संसद-सदस्य तथा ऐसे संसद सदस्य जो राज्य सभा के सदस्य नहीं हैं उनके पास पड़ी बकाया राशि का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा; और

(घ) 30 जून, 1998 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के संसद सदस्यों (जो चुनाव हार चुके हैं अथवा सेवा निवृत हो गए हैं) के पास बची बकाया राशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) 1995-96 और 1996-97 के प्रत्येक वर्ष में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य को 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। उत्तर प्रदेश में 30.11.1998 तक वर्ष 1997-98 के लिए 50-50 लाख रुपए की पहली और दूसरी किश्तें क्रमशः 119 और 102 संसद सदस्यों के वास्ते अवमुक्त की जा चुकी है।

(ख) 31.3.1998 तक उत्तर प्रदेश राज्य के संसद सदस्यों के संबंध में रिपोर्ट किए गए व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा "अनुपत्र" में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 185 अनुपत्र सं॰ 38]।

(ग) और (घ) संसद सदस्य के बदल जाने के मामले में संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की अधिशेष निधियों के उपयोग की प्रक्रिया संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैरा 3.9 में निर्धारित की गई। उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्रतियां सभी संसद सदस्यों को परिचालित कर दी गई हैं।

Allotments from MPLADS for Private Organisations

1365. SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many of the M.P. Local Area Development Scheme are being allotted to private colleges recognised by the UGC, private youth and women organisation etc. which are recognised by Government for the construction of Community Halls, buildings etc.; and

(b) the extent of such allotments made by M.Ps and accepted by the Local Government authorities in Srikakulam District of Andhra Pradesh?